"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार

****

‘हर काम देश के नाम

नई दिल्ली,आश्विन 09, 1945
रविवार, अक्टूबर 01, 2023

रक्षा मंत्री ने 276वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान रक्षा लेखा विभाग की कई डिजिटल पहलों का अनावरण किया

शुरू की गई पहलों में रक्षा मंत्रालय के लिए एक एकीकृत रक्षा वित्त डैशबोर्ड 'सारांश' भी शामिल है

भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ सुदृढ़ सशस्त्र बलों की आवश्यकता है; वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग महत्वपूर्ण: श्री राजनाथ सिंह

बदलते समय की जटिलताओं से निपटने के लिए डीएडी से आईआईएम और आईसीएआई जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करने का आह्वान किया

"उपयोगकर्ता एजेंसी की मांग का यथार्थवादी मूल्यांकन और उत्पाद के बाजार की समझ विवेकपूर्ण वित्तीय सलाह के लिए अनिवार्य"

अनुसंधान के लिए एक स्थायी समिति स्थापित करने और फील्ड अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता वाली बाजार खुफिया जानकारी प्रदान करने का सुझाव दिया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट में 01 अक्टूबर, 2023 को 276 वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) की कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में रक्षा मंत्रालय के लिए एक एकीकृत रक्षा वित्त डैशबोर्ड 'सारांश' शामिल है जो रक्षा मंत्रालय के लेखा, बजट और व्यय का सारांश है। इनमें विश्वास जो बिल सूचना और कार्य विश्लेषण प्रणाली है तथा ई-रक्षा आवास भी शामिल हैं।

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में डीएडी को रक्षा वित्त का संरक्षक बताया और पारदर्शी एवं कुशल प्रणाली के माध्यम से देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में इसके प्रयासों की सराहना की। लेखांकन को एक व्यक्ति, संगठन और राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, "हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। उन्होंने इष्टतम उत्पादन

निकालने के दौरान संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए डीएडी की सराहना की।

श्री राजनाथ सिंह ने कई डिजिटल पहलों के लिए डीएडी की सराहना करते हुए, विभाग की दक्षता और कामकाज को और बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने डीएडी के अधिकारियों को लगातार विकसित हो रहे समय से उत्पन्न जटिलताओं से निपटने के लिए अपनी पेशेवर क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया ताकि आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा सकें और उन्हें अपनाया जा सके।

रक्षा मंत्री ने वित्तीय सलाह को डीएडी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बताया। उन्होंने उनसे वित्तीय सलाह देते समय दो व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखने का आग्रह किया - उपयोगकर्ता एजेंसी की मांग का यथार्थवादी मूल्यांकन और उत्पाद के बाजार की समझ। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया कि क्या किसी उत्पाद को खरीदने की आवश्यकता है या नहीं और क्या समान या अधिक प्रभावशीलता वाला समान उत्पाद बाजार में कहीं और कम लागत पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस समझ से वित्तीय सलाह की गुणवत्ता और बढ़ेगी।

इस तरह की समझ विकसित करने के लिए, श्री राजनाथ सिंह ने एक आंतरिक तंत्र, अनुभवी लोगों की एक स्थायी समिति के निर्माण का सुझाव दिया जो बाजार की ताकतों का अनुसंधान और अध्ययन कर सके और क्षेत्र अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता वाली बाजार खुफिया जानकारी प्रदान कर सके। "बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान आंतरिक आर्थिक खुफिया और अनुसंधान टीमों का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर, डीएडी को बाजार अनुसंधान और खुफिया जानकारी के लिए एक इन-हाउस टीम विकसित करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने बाजार की स्थितियों के व्यापक अध्ययन के लिए उद्योग संघों, बिजनेस स्कूलों आदि के साथ सहयोग की भी सिफारिश की।

रक्षा मंत्री ने आंतरिक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके और तुरंत समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल समस्या से जल्दी निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि विभाग में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा।

श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को साकार करने में डीएडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, 'अगर हम एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की जरूरत होगी। इसलिए, हमारे पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। सेवाओं की मांग और उपलब्ध संसाधनों के आवंटन के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए।

रक्षा मंत्री द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

सारांश

सारांश (रक्षा मंत्रालय के लिए लेखा, बजट और व्यय का सारांश) की अवधारणा और विकास रक्षा लेखा विभाग में चल रहे विभिन्न आईटी प्रणालियों के विभिन्न डेटाबेस पर डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाकर भुगतान, लेखा, बजट आदि पर पूरे भारत में रक्षा वित्तीय डेटा के अधिक सटीक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

यह एनालिटिक्स टूल कई एप्लिकेशन/डेटा स्रोतों से वित्तीय डेटा को एकीकृत, संकलित, सैनिटाइज और मानकीकृत करता है और डैशबोर्ड की विशेषताओं के साथ एक वास्तविक समय व्यापक मंच प्रदान करता है: रुझानों को विज़ुअलाइज़ करना, मैट्रिक्स प्रदर्शित करना, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, रिपोर्टों आदि पर ग्राफ़ तैयार करना आदि इसके काम हैं। सारांश उच्च प्रबंधन के लिए एक पूर्ण डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा जिसमें केंद्रीकृत निगरानी के लिए सभी रक्षा व्यय की एक नज़र दृश्यता और सभी रक्षा संगठनों के लिए डेटा-संचालित निर्णयों की दिशा में प्रगति होगी।

बिश्वास

बिश्वास विभिन्न पीसीएसडीए/सीएसडीए के लिए डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर रिपोर्ट सहित बिल प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया प्रवाह की निगरानी और विश्लेषण के उद्देश्य से विभिन्न इन्फोग्राफिक्स प्रदर्शित करेगा। यह एक नियंत्रक कार्यालय के लिए विभिन्न कार्यालय स्वचालन प्रणालियों के माध्यम से प्रवाहित होने वाले सूक्ष्म डेटा के इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन के साथ बिल प्रोसेसिंग का वास्तविक समय विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

ई-रक्षा आवास

ई-रक्षा आवास एक केंद्रीकृत और व्यापक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे रक्षा सेवाओं के भीतर किराए पर लेने योग्य भवनों के लिए समय पर किराया और संबद्ध शुल्क बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने और सरकारी खातों में किराए और संबद्ध शुल्कों की त्वरित रिमिशन की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह पैकेज किराया और संबद्ध प्रभारों जैसे बीएसओ, एएओ (बीएसओ), एओ (जीई), पीएओ, पीसीएसडीए/सीएसडीए कार्यालय आदि के उत्पादन, वसूली और रिमिशन में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मंच के रूप में कार्य करता है।

इस अवसर पर, श्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख विभागीय परियोजनाओं को लागू करने में अनुकरणीय पहल का प्रदर्शन करने हेतु पांच टीमों को उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए – प्रशिक्षण पद्धति के नए प्रतिमान अपनाने के लिए; रक्षा लेखा विभाग में एसएएस परीक्षाओं के संचालन में कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) प्रणालियों का कार्यान्वयन; सारांश रक्षा मंत्रालय डैशबोर्ड का कार्यान्वयन; डॉल्फिन 2.0 का कार्यान्वयन, भारतीय सेना के जेसीओ/अन्य रैंकों के

लिए वेतन और भत्तों के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के विकास के लिए।

इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) श्रीमती रसिका चौबे, रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री एसजी दस्तीदार और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एबीबी/एलपी